



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7800-DB

आरक्षित:-18.12.2025

प्रदत्त किया गया:-13.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5242/2025

आयुष दीक्षित

....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : दीनानाथ मिश्रा, राज कुमार, राजर्षि गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, नवीन तिवारी, विमलेंदु त्रिपाठी

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं श्री राजर्षि गुप्ता और श्री डीएन मिश्रा एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री विमलेंदु त्रिपाठी को सुना गया और हमने अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका अपीलकर्ता-आवेदक आयुष दीक्षित की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें सत्र परीक्षण संख्या 1363/2020 (राज्य बनाम आयुष दीक्षित) में, जो कि आईपीसी की धारा 302, 504, 384 के अंतर्गत मामला संख्या 57/2020, पुलिस स्टेशन- डेरापुर, जिला- कानपुर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देहात से संबंधित है, और सत्र मामला संख्या 1362/2020 (राज्य बनाम आयुष दीक्षित) में, जो कि शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत मामला संख्या 58/2020, पुलिस स्टेशन- डेरापुर, जिला- कानपुर देहात से संबंधित है, इस मामलों के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 06.03.2020 को रात लगभग 9:30 बजे, शिकायतकर्ता का बेटा अमित उर्फ रामजी शुक्ला अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी अपीलकर्ता आयुष आया और पैसे मांगने लगा। जब बेटे ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसके सिर और गर्दन पर एक-एक गोली चलाई। शिकायतकर्ता और आसपास के लोग अमित को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन अपीलकर्ता मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक के सिर और गर्दन पर गोली लगने से दो चोटें आई थीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान से मेल नहीं खातीं; डॉक्टर के अनुसार, मृतक के शरीर पर केवल एक प्रवेश और एक निकास घाव पाया गया था; अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक को निकट से चलाई गई गोली से चोट लगी थी, लेकिन मृतक के शरीर पर झुलसने, काला पड़ने या कोई अन्य चिन्ह के निशान नहीं थे; निचली अदालत ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कथित घटना 06.03.2020 को हुई थी और दो गवाहों, मुकुंद और अरुण कुमार के बयान कथित घटना के ढाई महीने बाद दर्ज किए गए थे, जिसे जांच अधिकारी, यानी गवाह संख्या 5 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था; सभी चश्मदीद गवाह हितधारक हैं और गवाह संख्या 1 मृतक के पिता हैं; गवाह संख्या 3 मृतक के मामा हैं और गवाह संख्या 2 मृतक के करीबी दोस्त और ग्राहक हैं। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, पिस्तौल में नाइट्राइट और कॉपर पाए गए थे, लेकिन कथित घटना में प्रयुक्त कारतूस में ये नहीं पाए गए थे; अभियोजन पक्ष के गवाहों और सूचनादाता के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों से पहले, उन्होंने हथियार यानी देसी पिस्तौल के इस्तेमाल का खुलासा नहीं किया था, जिसे अपीलकर्ता ने शव/घायल/मृतक के पास फेंका था; अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक के शव को मृतक के भाई सुमित शुक्ला द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा फाउटी की रिपोर्ट दी गई थी; विद्वान विचारण न्यायालय ने 08.04.2025 को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णय और आदेश पारित करते समय जांच रिपोर्ट पर विचार नहीं किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीडब्ल्यू-3, जिसने जांच रिपोर्ट के अनुसार घटना को नहीं देखा था, ने मुकदमे के दौरान विरोधाभासी बयान दिया था। पीडब्ल्यू-1 ने कहा कि मृतक को दो गोली के घाव लगे थे, एक सिर पर और दूसरा गर्दन पर, जबकि पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 ने कहा कि एक घाव गर्दन पर और एक ठोड़ी पर लगा था। कथित घटना रात 9:30 बजे घटी, लेकिन घटनास्थल के नक्शे और जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बरामदगी ज़ापन से प्रकाश का कोई स्रोत स्पष्ट नहीं है; अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी और 8 अप्रैल 2025 के फैसले से यह स्पष्ट नहीं होता कि जबरन वसूली के रूप में कितनी रकम की मांग की गई थी; अभियोजन पक्ष के अनुसार, जबरन वसूली और अवैध मांग की कथित घटना के समय तीन गवाह मौजूद थे, लेकिन कथित मृतक को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया; इस आपराधिक मामले में अपीलकर्ता की संलिप्तता दर्शाने वाला कोई ठोस सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है; अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी अनुमान और संदेह पर आधारित है। अपीलकर्ता 7 मार्च 2020 से जेल में है और वर्तमान मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. सूचनादाता के अधिवक्ता और मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि गवाह संख्या 1, 2 और 3 की मौखिक गवाही को केवल चिकित्सा साक्ष्य से विरोधाभास होने के कारण नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपरोक्त गवाहों की मौखिक गवाही की पुष्टि करती है।

6. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्युकालिक चोटें पाईं:

"(i) दाहिनी ओर गर्दन पर 1 सेमी x 1 सेमी आकार का प्रवेश घाव, मध्य से 2.5 सेमी ऊपर और दाहिनी हंसली की हड्डी के किनारे से थोड़ा हटकर, अंदर की ओर मुड़ा हुआ।

(ii) छाती के दाहिनी ओर पीठ पर 1 सेमी x 1 सेमी आकार का निकास घाव, किनारा अंदर की ओर मुड़ा हुआ, कंधे की हड्डी के मध्य से बाईं ओर मध्य तक 10 सेमी की दूरी पर।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) घाव संख्या 1 और 2 की जांच करने पर दाहिनी ओर फुफ्फुस झिल्ली फटी हुई पाई गई; निकास घाव संख्या 2 तीसरी और चौथी पसलियों के बीच (अंतर-पसली स्थान) में पाया गया।

(iv) ठुंडी के मध्य में 5 सेमी x 1 सेमी आकार का काला घाव, निचले होंठ से ठीक 3 सेमी ऊपर।"

7. साक्ष्य गवाह-4, शव परीक्षण चिकित्सक ने राय दी है कि घाव संख्या 1 प्रवेश घाव है और घाव संख्या 2 निकास घाव है। घाव संख्या 1 के आसपास कोई झुलसने के निशान, चिन्ह या कालापन मौजूद नहीं था। यदि रिवॉल्वर या पिस्तौल से गोली चलाई गई हो, तो 3-4 इंच की दूरी से गोली चलाने पर जलने के निशान पड़ते हैं; 2-3 फीट की दूरी से गोली चलाने पर घाव के आसपास कालापन पाया जाता है और 4-6 फीट की दूरी से गोली चलाने पर घाव के आसपास टैटू जैसे निशान पाए जाते हैं। उन्होंने राय दी है कि चोट संख्या 1 निकट दूरी से गोली चलाने से नहीं हुई है।

8. इसलिए, गवाहों की प्रत्यक्षदर्शी गवाही, जिसमें मृतक की कमीज का कॉलर पकड़कर निकट दूरी से गोली चलाने की बात कही गई है, ऊपर बताए गए चिकित्सा साक्ष्य और गवाह संख्या 4 के बयान के संदर्भ में विश्वसनीय नहीं लगती है।

9. सामान्यतः, यदि प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सा साक्ष्य में असंगति हो, तो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को ही मान्य माना जाता है; लेकिन यदि मृतक के शव परीक्षण चिकित्सक की जांच के बाद चिकित्सा साक्ष्य सही पाया जाता है और मौखिक साक्ष्य से विश्वास नहीं होता है, तो अभियोजन पक्ष के संस्करण पर अविश्वास किया जा सकता है और उसे खारिज किया जा सकता है (देखें: **सुनील कुंडू बनाम झारखंड राज्य, 2013 एससीसी (क्रिमिनल) 427; चनाली मद्दीलेटी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2011 2 एससीसी (क्रिमिनल) 445; पुरुषोत्तम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1980 एआईआर (एससी) 1873 और निरंजन प्रसाद और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1996 एआईआर एससी 3010**)।

10. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय के समक्ष प्रतिदिन दो सौ से अधिक आपराधिक अपीलें सूचीबद्ध हैं और सभी का गुण-दोष के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर निर्णय लेना मानवीय रूप से संभव नहीं है, निकट भविष्य में इस अपील की सुनवाई की संभावना बहुत कम है, इसलिए आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

11. उपर्युक्त अपराध में दोषी ठहराए गए और सजा पाए आवेदक-अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

12. इस अपील के लंबित रहने के दौरान आवेदक-अपीलकर्ता को दी गई सजा भी निलंबित रहेगी।

13. आवेदक-अपीलकर्ता जमानत पर रहते हुए इस न्यायालय की अनुमति के बिना अपने नाम पर किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, हस्तांतरण या उस पर कोई प्रभार नहीं लगाएगा।

14. व्यक्तिगत और जमानती मुचलके प्रस्तुत होते ही, संबंधित न्यायालय द्वारा उनकी फोटोकॉपी तुरंत इस न्यायालय को अभिलेख में रखने के लिए भेजी जाए।

15. अपीलकर्ता-आवेदक को जेल से रिहाई की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर जुर्माने का 50% जमा करने का निर्देश दिया जाता है। जुर्माने का शेष 50% आपराधिक अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार वसूल किया जाएगा।

अपील पर आदेश

17. विचारण न्यायालय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

18. कार्यालय को पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

19. अपील को उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

13 जनवरी, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।